नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 020
दि. 20.05.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

इंडिया-नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, ग्रीन टेक्नोलॉजी साझेदारी पर जोर

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ और मल्टी-लैटरलिज्म के प्रति साझा प्रतिबद्धता भारत और नॉर्डिक देशों को नैचुरल पार्टनर्स बनाती है। प्रधानमंत्री ने समिट के आयोजन के लिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी और सस्टेनिबिलिटी में साझा प्राथमिकताएं दोनों पक्षों के रिश्तों को नए अवसरों से भर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आठ वर्ष पहले इंडिया-नॉर्डिक समिट फॉर्मेट की शुरूआत की गई थी।

व्यापार और निवेश में तेजी

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले 10 वर्षों में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग चार गुना बढ़ा है। वहीं, नॉर्डिक देशों के निवेश फंड भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के अहम साझेदार बनकर उभरे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में करीब 200% की वृद्धि हुई है। तेजी से बढ़ते व्यापार और निवेश ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को मजबूती देने के साथ-साथ नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी सकारात्मक योगदान दिया है और हजारों नई नौकरियां पैदा की हैं।

ट्रेड एग्रीमेंट्स से नए दौर की शुरूआत

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य ईएफटीए देशों के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया गया है। इसके अलावा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि इन महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों के जरिए भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरूआत होने जा रही है।

ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन साझेदारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देशों ने संबंधों को 'ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप' का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के जरिए आइसलैंड की जियो-थर्मल और फिशरीज विशेषज्ञता, नॉर्वे की ब्लू इकॉनमी और आर्कटिक विशेषज्ञता तथा सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सस्टेनिबिलिटी क्षमताओं को भारत के बड़े पैमाने के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही स्वीडन की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ-टेक विशेषज्ञता को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर दुनिया के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विकसित किए जाएंगे।

रिसर्च, स्किल और टैलेंट मोबिलिटी पर फोकस

पीएम मोदी ने कहा कि भारत-नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रिसर्च और इनोवेशन सहयोग भी है। इसे मजबूत करने के लिए यूनिवर्सिटीज, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आर्कटिक और पोलर रिसर्च में सहयोग को और गहरा करेंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

वैश्विक मुद्दों पर साझा रुख

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक तनाव और संघर्ष के मौजूदा दौर में

भारत और नॉर्डिक देश मिलकर रूल्स-बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और वेस्ट एशिया समेत सभी संघर्षों के शीघ्र समाधान और शांति प्रयासों का समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मल्टीलेटरल संस्थाओं में सुधार आवश्यक और तत्काल जरूरत है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी सभी देशों का स्पष्ट और एकजुट रुख है - 'नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स।'

'संबंध' शब्द से जोड़ी साझेदारी की भावना

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने 'संबंध' शब्द का उल्लेख करते हुए कहा कि कई नॉर्डिक भाषाओं में भी इस शब्द का अर्थ कनेक्शन, रिलेशन और बॉन्ड होता है। हिंदी में भी 'संबंध' का अर्थ यही है। उन्होंने कहा कि यह केवल शब्दों की समानता नहीं, बल्कि विचारों की निकटता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से हर क्षेत्र में आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने तथा इंडिया-नॉर्डिक पार्टनरशिप को साझा समृद्धि, इनोवेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर का मॉडल बनाने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जो चौंक गईं आइसलैंड की प्रधानमंत्री? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय देश आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर से मुलाकात की। पीएम मोदी और क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद 'संबंध' शब्द की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही भारत और आइसलैंड के बीच इस शब्द की भाषाई और भावनात्मक गूंज का जिक्र किया।

आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर ने कहा, 'हमने मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड से भारत में आने वाले निवेश में बढ़ोतरी का जिक्र किया है।

क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर ने आगे कहा, 'ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दोनों देश मिलकर कर सकते हैं और मुझे बस एक बात कहनी है, मुझे वह शब्द 'संबंध' बहुत पसंद है। यह पूरी तरह से आइसलैंडिक शब्द जैसा लगता है। लोग इस भाषा के प्रति बहुत समर्पित होंगे, प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि लोगों को इसी की जरूरत है। आज उन्हें और अधिक 'संबंधों' की जरूरत है।'

आइलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा, 'पीएम मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल हमारी सोच की निकटता की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया था। आज, मैंने 'संबंध' शब्द का कई बार इस्तेमाल किया।'

पीएम क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर ने बताया, 'कई नॉर्डिक भाषाओं में, संबंध शब्द का अर्थ है जुड़ाव, रिश्ते, एक बंधन। हिंदी में भी, संबंध का वही अर्थ होता है। यह सिर्फ शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारी सोच की निकटता को दर्शाता है।'

आइसलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा, 'आइए हम हर क्षेत्र में अपने बीच के बंधनों को और मजबूत करें और भारत-नॉर्डिक साझेदारी को साझा समृद्धि, नवाचार और एक टिकाऊ भविष्य का एक आदर्श बनाएं।'

इस शिखर सम्मेलन में स्थिरता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और उन्नत तकनीकी सहयोग पर जोर दिया गया। भारत और नॉर्डिक देशों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेता एक साथ इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने, ताकि भविष्य के सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।

उपराष्ट्रपति ने मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी (सेवानिवृत्त) के निधन पर शोक व्यक्त किया

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी (सेवानिवृत्त) के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मेजर जनरल श्री खंडूरी के निधन से देश ने एक विशिष्ट सैनिक, एक सक्षम प्रशासक और असाधारण सत्यनिष्ठा वाले राजनेता को खो दिया है।

विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र, प्रशासनिक कार्रवाइयों में संवेदनशीलता बरतने की अपील की

(जीएनएस)।

लखनऊ, राजधानी लखनऊ में भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर व्यापारियों के प्रति प्रशासनिक कार्रवाइयों में संवेदनशीलता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने जनहित और सुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, विशेषकर छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के मामलों में।

डॉ. सिंह ने अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास एवं सुशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है और जनता का सरकार पर विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। ऐसे में आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों का भी संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील नहीं हो

उन्होंने आगाह किया कि छोटी-छोटी बातों पर अत्यधिक चालान, अनावश्यक नोटिस या बिजली विच्छेदन जैसी कठोर कार्रवाइयां जन-असंतोष पैदा कर सकती हैं। इससे विपक्ष को सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर मिल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माफिया और भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील नहीं होनी चाहिए।

"बीमारू' राज्य से विकास की धुरी बना उत्तर प्रदेश', सीएम योगी ने गिनाईं यूपी मॉडल की उपलब्धियां

(जीएनएस)।

लखनऊ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नए भारत' की विकास यात्रा का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि जो प्रदेश कभी 'बीमारू' राज्य कहा जाता था, वही आज देश की अर्थव्यवस्था और विकास की धुरी बन चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकारी संघवाद पर आधारित 'टीम भारत' के विजन ने राज्यों के बीच समन्वय और विकास की नई दिशा तय की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर जैसे कभी चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्र में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होना इस बात का प्रमाण है कि देश तेजी से बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले नौ वर्षों में कानून-व्यवस्था, निवेश, रोजगार, आधारभूत ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है।

प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति लागू की गई है, जिसके चलते कानून का शासन जमीन पर उतारा गया है।

मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर सर्जिकल वार किया जा चुका है। वर्ष 2016 में प्रदेश में केवल दो साइबर थाने थे, जबकि अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने हैं। उप्र ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है।

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 2.33 लाख से अधिक कामन सर्विस सेंटर संचालित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने यूपी एआइ मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये तथा क्वांटम फोटोनिक्स जैसी नई तकनीकों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिमाह 1.30 करोड़ बच्चों और 22 लाख गर्भवती व धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 'संभव अभियान' और 'संभव 5.0' के जरिए कुपोषण को कम करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 9.56 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को जोड़ा गया है और 5.73 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। देश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अधिक आवास उपलब्ध कराने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के पहले चरण में 20 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया है।

उत्तर पूर्वी राज्यों के कारीगर और बुनकर समूह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने आज (19 मई, 2026) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से

मुलाकात की।

कारीगरों और बुनकरों ने 26 जनवरी, 2026 को आयोजित 'एट होम' रिसेप्शन के दौरान निमंत्रण किट तैयार करने और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उदाहरण के लिए, नागालैंड के कारीगरों ने केले के रेशे और बांस का उपयोग करके टोकरियां बनाईं, असम के बुनकरों ने शॉल बनाए। मणिपुर के कारीगरों ने काली मिट्टी के बर्तन बनाए और सिक्किम के कारीगरों ने प्राकृतिक रेशों का उपयोग करके उत्पाद तैयार किए।

नॉर्वे में पत्रकार के सवाल को लेकर राहुल का पीएम मोदी पर तंज, कहा- 'कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम'

(जीएनएस)।

राहुल गांधी ने नॉर्वे की एक पत्रकार का वीडियो शेयर करते हुए ये टिप्पणी की। वीडियो के जरिये दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नॉर्वे में पत्रकारों के सवाल नहीं लेने का दावा करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। राहुल ने अपने हैंडल पर कहा, 'जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की जरूरत नहीं पड़ती।'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्वे की एक पत्रकार का वीडियो शेयर करते हुए ये टिप्पणी की। वीडियो के जरिये दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया।

राहुल गांधी ने कहा, 'जब दुनिया एक प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है?' राहुल ने मोदी को 'कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम' भी कहा।

वीडियो में पत्रकार हेले लिंग को यह पूछते हुए सुना जा सकता है, 'प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते?'

बाद में हेले लिंग ने पर घटना की फुटेज शेयर करते हुए लिखाः 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 157वें स्थान पर है।'

प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों पांच देशों की छह दिवसीय यात्रा पर हैं। वह इस यात्रा क्रम में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ प्रमुख द्विपक्षीय कार्यक्रम के लिए सोमवार को ओस्लो पहुंचे थे।

एक्यूआई के 'खराब' श्रेणी में पहुँचने पर सीएक्यूएम ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप चरण-क लागू किया

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान(ग्रैप) का चरण-क लागू कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 208 पर पहुँच गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।यह निर्णय दिल्ली- एनसीआर में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूवार्नुमानों के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रैप उप-समिति द्वारा लिया।

सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- जगह कम है तो क्या दिक्कत?

(जीएनएस)।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमाज वाले बयान पर पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए नियम-कानून बने हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सबसे अधर्मी पार्टी है, तो वह भाजपा है .उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है.

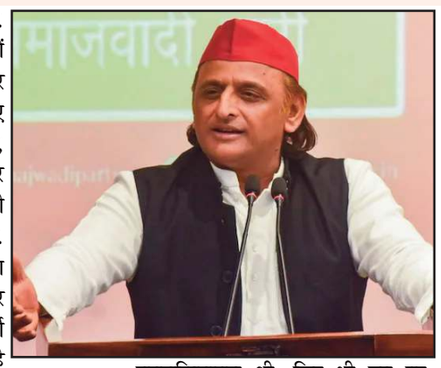

अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में अधिवक्ता संघ के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे, जिनके हाथों में रामचरितमानस थी, फिर भी उन पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें पीटा गया. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा खुद को सनातन की पक्षधर मानती है, तो उसे 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना पर चलना चाहिए.

अखिलेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि न तो स्मार्ट सिटी बन पाई और न ही स्मार्ट मीटर योजना टिक सकी, जिन्हें हटाना पड़ा. ऐसे में सरकार के कामकाज पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मई को हिंदी अखबार अमर उजाला के एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाती. उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए होती हैं और किसी को भी चौराहों या सड़कों को रोककर सार्वजनिक जीवन बाधित करने का अधिकार नहीं है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नमाज के लिए निर्धारित स्थान मौजूद हैं और लोगों को वहीं जाकर इबादत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि संख्या अधिक है तो लोग शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं.

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग समेत 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी

कैबिनेट ने लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार और नये आठ मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद बाद आयोजित यूपी कैबिनेट में सोमवार को 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को हरी झंडी दे दी गई। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के फैसलों से यह तो तय है कि सरकार चुनावी दौर और विकास दोनों को साधने की तैयारी में है।

यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का था, जिसको भी मंजूरी प्रदान की गई। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला लिया गया।

इसके साथ लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने और लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि आवंटन के एमओयू को

मंजूरी दी है।

पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मिली मंजूरी

योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय कर बड़ी समस्या दूर कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में नए ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा।

यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी, उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा।

कैबिनेट के फैसले:

समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी, प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में होगा संशोधन, यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा, मिजार्पुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ, लखनऊ मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी, चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी, लखनऊ के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर एमओयू पास, लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी, मेट्रो विस्तार से राजधानी में ट्रांसपोर्ट होगा मजबूत, पशु चिकित्सा छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इंटर्नशिप भत्ता ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹12 हजार, वेटरनरी छात्रों को अब मिलेगा ₹12 हजार मानदेय, मिजार्पुर पूलिंग उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी, ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव पर लगी मुहर, यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी, लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर, सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता साफ, आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर, आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को मंजूरी

कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की आम सभा आयोजित

(जीएनएस)।

कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की एक सभा जूही बसंती नगर कानपुर में हुई सभा की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष श्री बनवारीलाल कंछल ने की। संचालन जिलाध्यक्ष आशीष सचान ने किया। सभा में प्रमुख रूप से ऑनलाइन ट्रेडिंग में सरकारी कर्मचारियों की भांति व्यापार को स्वास्थ्य बीमा व दुकान चलने पर एक करोड़ का बीमा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई चेयरमैन सुबोध चोपड़ा ने व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प दोहराया और प्रशासन को आग्रह किया जीएसटी विभाग खाद विभाग बिजली विभाग को व्यापारियों से संतुलन बनाने का प्रयास करें जिलाध्यक्ष आशीष सचान ने कहा सीएम ग्रिड योजना तहत हो रहे कार्यों

में विलंब के कारण खुदी सड़कें धूल आदि से व्यापार नहीं हो पा रहा है जो की चिंता जनक है। कानपुर युवा उद्योग व्यापार अध्यक्ष आयुष द्विवेदी ने नौ मीटर से कम चौड़ी सड़कों के किनारे भवनों के नव निर्माण के लिए नक्शा न पास होना अत्यंत कष्टदायी है जिससे पुरानी इमारतों को बनाना मुश्किल हो गया जबकि कानपुर नगर का मुख्य थोक बाजार गलियों में ये ही है। महामंत्री अनूप तिवारी ने संगठन के विस्तार करने के लिए अपने विचार रखे महामंत्री मुहम्मद कलीम ने परेड मैदान में व्यापारियों को बेदखली मामले को उठाया। इस मौके पर मनोज तिवारी यशपाल सिंह भदौरिया मो अजीम मनीष द्विवेदी सुरेश अग्रवाल अंशु बाजपेई राजीव अवस्थी मुन्ना कुरैशी, विजय अवस्थी गौरव निगम अवधेश शुक्ला राजेश चौहान विनीत सिंह दीपक शुक्ला शैलेन्द्र शुक्ला रिंकू भाई मनी त्रिवेदी फैसल आसिफ नितिन श्रीवास्तव ज्ञानू राठौड़ मो शाहिद वसीक अहमद हिमांशु सैनी आदि रहे

सड़कों में नमाज पर साध्वी प्राची ने किया सीएम योगी के बयान का समर्थन, बोलीं- 'सड़कें आम लोगों के...'

विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने सीएम योगी के नमाज वाले बयान का समर्थन किया है. साथ ही सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर प्रतिक्रिया दी.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचीं विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने सपा नेता राजकुमार भाटी के कथित विवादित बयान को लेकर जमकर हमला बोला. शिव चौक पर जलाभिषेक के बाद मीडिया से बातचीत में साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया. इस दौरान उन्होंने सड़क पर नमाज, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी.

मंगलवार को सिटी के शिव चौक पहुंचीं साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेता राजकुमार भाटी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महिलाओं का

अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साध्वी प्राची ने कहा कि जो लोग समाज और महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उन्हें उनकी भाषा में जवाब मिलना चाहिए.

कुछ नेता वोट के लिए समाज को बांटने का करते हैं काम

मीडिया से बातचीत के दौरान साध्वी प्राची काफी आक्रामक अंदाज में नजर आईं. उन्होंने कहा कि कुछ नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं. उन्होंने महिलाओं से जागरूक रहने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाने की अपील की.

सीएम योगी के बयान का किया समर्थन

इस दौरान साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि सड़कें आम लोगों के आने-जाने के लिए होती हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि परिवारों को अपनी बेटियों को जागरूक और संस्कारित बनाने की जरूरत है.

अपराध और अराजकता पर सख्त कार्रवाई जरूरी

उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. साध्वी प्राची ने देश में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग दोहराते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि अपराध और अराजकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

लखनऊ में लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने किया प्रदर्शन

(जीएनएस)।

फिरोजाबाद टूंडला। लखनऊ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को बार एसोसिएशन टूंडला के पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी और विरोध-प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रूमाल सिंह यादव के नेतृत्व में सुबह 11 बजे लामबंद हुए वकीलों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए एसडीएम अंकित वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने मांग की है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर मुकदमा दर्ज किया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने घायल वकीलों को मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान वकीलों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी उठाई।

इस दौरान प्रमुख रूप से राजकुमार यादव, मुकेश यादव, लीलाधर वर्मा, ममता सारस्वत, हरिओम शर्मा, योगेंद्र यादव, लाखन सिंह वर्मा, भंवर सिंह सोलंकी, संदीप यादव, धीरेंद्र शर्मा और दीपक रिछारिया आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

नौधा प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षा चौपाल का आयोजनः शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार पर मंथन

(जीएनएस)।

हरदोई बेहंदर प्राथमिक विद्यालय नौधा में खंड शिक्षा अधिकारी राजेश राम की अध्यक्षता और प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष 'शिक्षा चौपाल' का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और शिक्षण विधियों में नए नवाचारों पर विस्तार से चर्चा करना था।कार्यक्रम का कुशल संचालन प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष कमलेश पाल द्वारा किया गया। चौपाल में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य जगदीश चौरसिया उपस्थित रहे,जिनके लंबे शैक्षणिक अनुभव और मार्गदर्शन ने उपस्थित लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया।सरकारी विद्यालयों की सुविधाओं पर जोर कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक संघ की अध्यक्ष नीलिमा देशवाल नेअभिभावकों से संवाद करते हुए उन्हें निजी स्कूलों के बजाय सरकारी विद्यालयों पर भरोसा जताने की अपील की। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय केवल एक छलावा हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों में अधिक योग्य, शिक्षित स्टाफ और बेहतर सुविधाएंउपलब्धहैंअभिभावक-शिक्षक संवाद और निपुण भारत मिशन पर

चर्चाअनुपम द्विवेदी ने अपने संबोधन में ब्लॉक के वर्तमान और पूर्व एआरपी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बेहंदर ब्लॉक में शिक्षा की अलख जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में परिवार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।वहीं,एआरपी वर्तिका सिंह और महेंद्र सिंह ने 'निपुण भारत मिशन' के तहत विभागीय लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पूर्व प्रधानाचार्य जगदीश चौरसिया ने अपने वर्षों के अनुभव साझा करते हुए शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित किया।इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति

इस चौपाल को सफल बनाने में शिक्षक संघ के पदाधिकारी अरविंद कुमार उपाध्यक्ष, राम मिलन चक्रवर्ती संगठन मंत्री, जगबीर सिंह संगठन मंत्री, जहान सिंह संगठन मंत्री और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की उपाध्यक्ष विभा अवस्थी सहित भारी संख्या में ग्रामीण व अभिभावक उपस्थित रहे।टीम की तत्परता से सफल हुआ आयोजननौधा विद्यालय के स्टाफ और अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई।

शिक्षिका मधु कटियार, राम नारायण, जीनत परवीन तथा प्राथमिक विद्यालय रिठवे के प्रधानाध्यापक नीतीश कुमार, अवनीश कुमार, राजाराम, दीपक दिवाकर, राजेश वर्मा और रजनीश वर्मा ने पूरी तत्परता के साथ अभिभावकों को बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों और शिक्षकों के इस संकल्प के साथ हुआ कि वे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर आपसी समन्वय से प्रयास करते रहेंगे। अंत में प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने सभी आगंतुकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

रेल वैगन के स्क्रैप से तैयार इको हेरिटेज गार्डन बना ग्रीन इनोवेशन की मिसाल

जहाँ आमतौर पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्क्रैप को बेकार मान लिया जाता है, वहीं झाँसी का वैगन मरम्मत कारखाना उसी स्क्रैप से एक नई मिसाल पेश कर रहा है। अब यह कारखाना केवल वैगनों की मरम्मत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मक सोच का एक जीवंत उदाहरण बन गया है।

करीब डेढ़ सदी पुराना यह कारखाना वर्ष 1882 में स्थापित हुआ था, जब देश में रेलवे नेटवर्क विस्तार की शुरूआत हो रही थी। इंडियन मिडलैंड रेलवे ने झाँसी को इस महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चुना और 1895 में यहाँ स्टीम इंजन यात्री डिब्बों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। व

आज 84 एकड़ में फैला यह कारखाना भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा वैगन मरम्मत केंद्र बन चुका है, जहाँ हर महीने करीब 925 मालवाहक वैगनों की मरम्मत की जाती है। आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद से यहाँ डिफेंस वैगनों समेत सभी प्रकार के वैगनों की ओवरहॉलिंग की जाती है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता काफी उच्च मानी जाती है।

हालांकि, अब इस कारखाने की पहचान केवल उसके काम तक सीमित नहीं रही। वर्ष 2023 में शुरू की गई एक नई पहल ने इसे एक अलग मुकाम दिया है। मरम्मत के दौरान निकलने वाले स्क्रैप का उपयोग कर करीब 5 एकड़ क्षेत्र में "इको हेरिटेज गार्डन" तैयार किया गया, जो आज लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है।

इस गार्डन में स्क्रैप से तैयार किए गए इंडिया गेट और ताजमहल जैसे मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र हैं, जो देखने वालों को चौंका देते हैं। इसके अलावा ट्री हाउस, झोपड़ियाँ, फिश पार्क, अंब्रेला गार्डन, वॉल आर्ट और 3ऊ पोर्ट्रेट्स इसे एक अनोखा और जीवंत स्वरूप देते हैं। यह पहल स्पष्ट रूप से दशार्ती है कि अनुपयोगी समझी जाने वाली सामग्री को भी रचनात्मकता के माध्यम से उपयोगी और आकर्षक बनाया जा सकता है।

कारखाने में स्थापित रेल म्यूज़ियम भी अपनी अलग पहचान रखता है, जहाँ रेल मॉडल और कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय रेल की समृद्ध विरासत को नए और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

झाँसी का यह वैगन मरम्मत कारखाना अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है, जो यह संदेश देता है कि नई सोच और नवाचार से स्क्रैप भी सृजन की मजबूत नींव बन सकता है।

राजस्थान के मेड़ता को मिला बड़ा रेल गिफ्ट!

रोजगार के खुलेंगे नए द्वार, यात्रियों को मिलेगा बेहतर और समयबद्ध सफर

राजस्थान के रेल इतिहास में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मेड़ता रोड स्टेशन पर राज्य का पहला मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) शेड विकसित किया जा रहा है। करीब ₹60 करोड़ की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना न सिर्फ रेलवे की क्षमता बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा देगी।

यह शेड मौजूदा डीजल कार शेड को अपग्रेड करके आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। परियोजना के तहत पिट लाइनों का विद्युतीकरण, ट्रैक्शन इंस्टॉलेशन, सिविल कार्य, व्हील लेथ की स्थापना और अत्याधुनिक मेंटेनेंस सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। इसकी शुरूआत वर्ष 2022-23 में हुई थी और पूरा होने पर यह लगभग 50 MEMU रेक के रखरखाव में सक्षम होगा।

इस शेड के शुरू होने से रेलवे की मेंटेनेंस क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, जिससे ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी और संचालन ज्यादा सुचारू व कुशल होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवाओं को गति मिलेगी और अधिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों के उपयोग से किराया नियंत्रण में मदद मिलेगी जिससे यात्रा और किफायती होगी ।

MEMU शेड के निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर कई तरह के रोजगार भी उत्पन्न होंगे। इसमें तकनीकी स्टाफ, मेंटेनेंस वर्कर, इंजीनियर, ठेका श्रमिक, सुरक्षा कर्मी और सहायक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए अवसर बनेंगे। इसके अलावा आसपास छोटे व्यवसायों- जैसे दुकानों, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा।

कुल मिलाकर, मेड़ता रोड का यह टएटव शेड राजस्थान के लिए गेमचेंजर साबित होगा- जहां एक ओर यात्रियों को बेहतर सफर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई गति मिलेगी।

प्रतापराव जाधव ने आयुष ग्रिड पहल के तहत आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया

आयुष अनुदान पोर्टल अनुदान प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा: श्री प्रतापराव जाधव यह पोर्टल डिजिटल रूप से सशक्त और पारदर्शी आयुष इकोसिस्टम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है

(जीएनएस)।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल आयुष ग्रिड पहल के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जो मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, प्रसंस्करण, अनुमोदन और निगरानी को सुव्यवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

श्री प्रतापराव जाधव ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आयुष ग्रिड भारत सरकार की एक दूरदर्शी डिजिटल मंच के रूप में विकसित किया गया है।'

डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से आयुष क्षेत्र के लिए एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम स्थापित करना है। इस पहल के पीछे की सोच को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'व्यापार करने में सुगमता' और 'जीवन जीने में सरलता' के विजन से प्रेरित होकर, आयुष अनुदान पोर्टल को एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाकर सरकार के कागज रहित शासन के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

श्री जाधव ने कहा कि यह पोर्टल आयुष क्षेत्र की अनुदान प्रबंधन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस प्लेटफॉर्म के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा, 'इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में शत-प्रतिशत पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है।' उन्होंने यह भी बताया कि यह पोर्टल संगठनों और संस्थानों को पूरी तरह से ऑनलाइन

श्री जाधव ने कहा कि एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकरण से आवेदक संगठनों का प्रमाणीकरण और सत्यापन तेज, स्वचालित, विश्वसनीय और त्रुटिरहित हो जाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाएं, औषधीय पौधों की व्यवस्था, औषधि विनियमन, क्षमता निर्माण और वैश्विक पहुंच जैसे क्षेत्रों में एबीडीएम-अनुरूप आयुष ग्रिड पहल के तहत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जिससे पारदर्शी और नागरिक-हितैषी सेवा वितरण सुनिश्चित हो रहा है।

इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा; संयुक्त सचिव डॉ. कविता जैन, श्रीमती अलार्मेलमंगई डी. और सुश्री मोनालिसा डैश; साथ ही आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

जोधपुर में होगा अब सबसे आधुनिक वंदे भारत स्लीपर का मेंटिनेंस

₹360 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा देश का पहला समर्पित मेंटेनेंस डिपो

जोधपुर अब भारत के रेलवे आधुनिकीकरण का एक अहम केंद्र बनने जा रहा है। यहां देश का पहला वंदे

भारत स्लीपर ट्रेनों का समर्पित मेंटेनेंस डिपो तेजी से तैयार हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 फरवरी 2024 को शिलान्यास के बाद इस परियोजना का पहला चरणं

तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अब इस परियोजना को नई गति देते हुए रेल मंत्रालय ने फेज-2 के लिए ₹95 करोड़ का टेंडर जारी किया है। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग ₹360 करोड़ आंकी गई है।

इस डिपो की सबसे बड़ी खासियत इसकी क्षमता है। यहां 600 मीटर लंबी मेंटेनेंस ट्रैक सुविधा होगी, जिसमें एक साथ 24 स्लीपर कोच (करीब 3 पूरी ट्रेन सेट) का रखरखाव किया जा सकेगा।

फेज-2, जिसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, में अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इसमें प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग, मॉडर्न वर्कशॉप, सिम्युलेटर आधारित ट्रेनिंग सेंटर के साथ-साथ पिट लाइन्स, व्हील रैक सिस्टम, टेस्टिंग लैब, ड्रॉप पिट टेबल और बोगी ट्रांसफर सिस्टम शामिल होंगे। यहां थ्री टियर इंस्पेक्शन सिस्टम, हाई-टेक मशीनरी और एडवांस्ड टेस्टिंग टूल्स के जरिए ट्रेनों की उच्च स्तर की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

इस मेगा प्रोजेक्ट से जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्य से लेकर तकनीकी और संचालन से जुड़े हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके

अलावा स्थानीय व्यवसाय, जैसे- ट्रांसपोर्ट, होटल और छोटे व्यापारियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

वंदे भारत स्लीपर सेवाओं के विस्तार के साथ, जोधपुर का यह डिपो देश में लंबी दूरी की तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा के भविष्य को नई मजबूती देगा। साथ ही, यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

आम उपभोक्ता के लिए मुश्किल दौर

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक सप्ताह के अन्दर ही दूसरी बार बढ़ने के कारण दिल्ली में 97.77 रुपए से बढ़कर 98.64 रुपए हो गया। इससे महंगाई का बढ़ना तय है।

दरअसल पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का उपभोक्ताओं पर सापेक्ष प्रभाव पड़ता है। बसों के किराए, ट्रकों के ढुलाई की कीमत बढ़ेगी तो सब्जी, दूध और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसलिए पेट्रोल-डीजल के दाम भले ही 90 पैसे ही बढ़ा किन्तु चक्रीय प्रभाव के कारण उपभोक्ताओं को सेवाओं और वस्तुओं पर ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेंगी।

सच तो यह है कि मुद्रास्फीति और विकास दोनों एक साथ नहीं चलने को अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 7 प्रतिशत है जब थोक मूल्य सूचकांक देखें तो महंगाई दर 8.02 प्रतिशत हो गई। जब भारत की मुद्रास्फीति 3.5 प्रतिशत के नीचे रहती थी और जीडीपी यानि आर्थिक विकास दर 6.5 से 7.8 प्रतिशत तक रही तब भी मध्यमवगीय उपभोक्ता महंगाई की शिकायत करता था आज तो मामला बिल्वुल संवेदनशील हो गया है। आम उपभोक्ता के लिए बहुत ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जबकि सरकार के लिए भी चुनौतियां बहुत विकराल हो चुकी है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी बीमारी है जो उसकी विदेशी मुद्रा को खाकर डकार जाती है और वह देश भुगतान संतुलन कायम रख पाने में असमर्थ होता है। रही भारत की बात तो आज की तारीख में भारत के पास भले ही विदेशी मुद्रा भण्डार 690 बिलियन डालर मौजूद है किन्तु इसी तरह विश्व बाजार में तेल की कीमतों में आग लगी रहेगी तो देश का चालू वित्तीय घाटा आसमान पर होगा। ऐसी बीमार अर्थव्यवस्था से भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी।

बहरहाल सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता लाने के तीन तरह के कदम उठाने होंगे। पहला तो तात्कालिक। इसके तहत रूस से ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदे और कोशिश करे कि अपने विदेशी मुद्रा पर भुगतान का दबाव कम से कम पड़े। दूसरा है दीर्घकालीन व्यवस्था।

इसके तहत सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों का टंटा ही खत्म करना होगा।

ग्रीन एनजी और सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा वाहनों में इस्तेमाल हो, इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास होना चाहिए। तीसरा है एहतियात के तौर पर प्रयास होना चाहिए कि निजी वाहनों की बजाए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

लब्बोलुआब यह है कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण दुनिया को महंगाई की मुसीबतों से बच पाना असंभव है। इसलिए सरकार को बहुत सावधानी से भुगतान संतुलन, चालू वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने तथा आम उपभोक्ता को राहत देने के लिए बहुत ही सावधानी से वित्तीय नीतियों का निर्धारण एवं उनका अनुशरण करना होगा अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने के गंभीर परिणाम होंगे ऐसे में जब उपभोक्ता ठनठन गोपाल होगा तो कारोबार ठप होंगे और अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। इसीलिए सरकार को बड़ी सावधानी से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बारे में विचार करना होगा। चूंकि यह संकट हमारे देश की सरकार द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है और यह कब तक चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उपभोक्ता भी सेवाएं एवं वस्तुओं का इस्तेमाल अनावश्यक करने से बचें ताकि देश का रिजर्व समाप्त न हो अथवा खतरनाक रूप से सीमित न हो।

थलपति विजय ने पीएम मोदी को पत्र लिख किया यूरिया और डीएपी खाद की बिना रुकावट सप्लाई का अनुरोध

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय किसानों की समस्याओं को लेकर एक्शन मोड में हैं। विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक जरूरी पत्र लिखकर आने वाले खरीफ खेती के मौसम के लिए यूरिया और डीएपी खाद की निर्बाध सप्लाई का अनुरोध किया है।

(जीएनएस)।

चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा। इसमें उन्होंने 2026 के खरीफ खेती के मौसम के लिए तमिलनाडु को यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी उर्वरकों की बिना रुकावट सप्लाई की जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले विजय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से कपास पर लगने वाले 11 प्रतिशत आयात शुल्क को तत्काल हटाने का आग्रह किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य का कपड़ा और परिधान क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा

अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि तमिलनाडु की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में लगभग 48.27 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की जाती है, जबकि कुल कृषि खेती का क्षेत्रफल 62.25 लाख हेक्टेयर है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के लगभग 92 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जहां तमिलनाडु के पास भारत के कुल जल संसाधनों का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है, वहीं राज्य धान, बाजरा, तिलहन, कपास, गन्ना, सब्ज़ियां, फूल, फल, औषधीय और सुगंधित पौधे, मसाले और बागवानी फसलों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करता है।

डिमांड के मुकाबले कितनी कम सप्लाई?

पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने

10 मई, 2026 को पदभार संभालने के बाद से अलग-अलग क्षेत्रों के कामकाज की विभाग-दर-विभाग समीक्षाएं वे कर रहे हैं। उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उर्वरक निमार्ता अप्रैल और मई 2026 के महीनों के लिए अनुमानित जरूरतों के मुकाबले तमिलनाडु को 39,001 मीट्रिक टन यूरिया, 28,607 मीट्रिक टन डीएपी और 24,235 मीट्रिक टन पोटाश की सप्लाई करने में विफल रहे।

मुख्यमंत्री ने पत्र में दी चेतावनी

इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य भर में धान, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल और विभिन्न बागवानी फसलों जैसी फसलों की खेती की गतिविधियां इस समय जोरों पर हैं। चूंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मई के तीसरे सप्ताह में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के शुरू होने का अनुमान लगाया है और राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इसलिए किसानों ने आने वाले खरीफ मौसम के दौरान अधिकतम संभव क्षेत्र में फसल की खेती करने में गहरी रुचि दिखाई है। परिणामस्वरूप यूरिया और डीएपी उर्वरकों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उर्वरकों की कमी होती है, तो यह राज्य की खाद्य सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा बन सकता है।

विजय का प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह, कपास उत्पादकों पर दें ध्यान

इससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपास पर लगने वाले 11 प्रतिशत आयात शुल्क को तत्काल हटाने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य का कपड़ा और परिधान क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में सीएम विजय ने कहा था कि कपास और धागे की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी ने कपड़ों के निमार्ताओं पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है और इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों मजदूरों की रोजी-रोटी को खतरे में डाल दिया है। तमिलनाडु को भारत का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात करने वाला राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है।

शून्य के भीतर: चेतना का विद्रोह – रवि प्रकाश सिंह

लेखक, प्रशासक और चेतना, तकनीक तथा सभ्यता के भविष्य पर सार्वजनिक विचारक

"जब एक एल्गोरिद्म आपके अगले विचार की भविष्यवाणी आपसे पहले कर दे — तो क्या वह विचार अभी भी 'आपका' है?"

भूमिका

मानव इतिहास केवल औजारों के विकास की गाथा नहीं, बल्कि अपनी चेतना के विस्तार की निरंतर छटपटाहट है। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अक) के उस मुहाने पर खड़े हैं, जहाँ हम केवल मशीनें नहीं बना रहे, बल्कि अपनी चेतना का एक 'डिजिटल प्रतिरूप' रच रहे हैं। यह सृजन की वह अंतिम सीमा है जहाँ सृष्टा और सृष्टि का अंतर मिटने लगा है।

किंतु इस असीमित शक्ति के शोर में, हमारे भीतर का वह मौलिक मौन — 'शून्य' — संकट में है। यहीं से जन्म लेता है: चेतना का विद्रोह।

शक्ति का विस्फोट और विवेक का ठहराव

समस्या तकनीक में नहीं है। समस्या तकनीकी विकास की 'घातीय' गति और हमारी नैतिक परिपक्वता की धीमी चाल के बीच बढ़ते फासले में है।

एक उदाहरण पर्याप्त है: चैटजीपीटी को 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने में केवल 2 महीने लगे — जबकि इसके नैतिक दिशानिर्देश अभी भी समितियों में विचाराधीन हैं। हम मशीनों को रातों-रात अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मानवीय चरित्र का 'अपग्रेड' एक जटिल और पीढ़ीगत प्रक्रिया है।

ज्ञान हमें बताता है कि 'क्या संभव है', लेकिन विवेक पूछता है कि 'क्या उचित है'। आज हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, पर उस 'शून्य' की कमी है जहाँ सूचना, ज्ञान और बोध में बदल सके।

एल्गोरिद्म बनाम स्वतंत्र इच्छा

भविष्य का सबसे बड़ा संकट मशीनों की बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य की स्वेच्छा से स्वीकार की गई 'दासता' है। जब एल्गोरिद्म हमारे लिए यह तय करने लगें कि हमें क्या खरीदना है, क्या सोचना है और किससे घृणा करनी है, तो हम धीरे-धीरे अपनी 'स्वतंत्र चेतना' खोने लगते हैं।

2021 में फेसबुक की व्हिस्लब्लोअर फ्रांसेस हॉगन ने यह उजागर किया कि कंपनी के एल्गोरिद्म जानबूझकर ऐसी सामग्री को प्राथमिकता देते थे जो क्रोध और विभाजन को बढ़ावा देती है — क्योंकि यही सर्वाधिक जुड़ाव लाती है। यह महज एक कंपनी की कहानी नहीं, यह उस पूरी व्यवस्था का चेहरा है जो मनुष्य की भावनाओं को डेटा में बदलकर बेचती है।

सुविधा के नाम पर हम अपनी विशिष्टता को डेटा के हवाले कर रहे हैं। 'चेतना का विद्रोह' इसी मशीनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ मनुष्य की वह पुकार है, जो उसे एक 'जैविक डेटा' बनने से रोककर पुनः 'मनुष्य' के रूप में स्थापित करती है।

अस्तित्व का संघर्ष और जैविक करुणा

भारतीय दर्शन में 'शून्य' रिक्तता नहीं, बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। आज का डिजिटल तंत्र हमें सूचनाओं से इतना भर देता है कि हम अपने भीतर के उस शून्य (स्व) का साक्षात्कार ही नहीं कर पाते।

अकहमें 'पूर्ण स्मृति' का वरदान दे रही है — लेकिन क्या हम जानते हैं कि भूलना एक 'जैविक करुणा' है?

न्यूरोसाइंस बताता है कि मस्तिष्क नींद के दौरान अनावश्यक स्मृतियों की छटनी करता है — यही हमारी मानसिक स्वच्छता और आंतरिक नवीनीकरण है। जब हर पल रिकॉर्ड हो, हर भूल आर्काइवड हो, हर कमजोरी डेटाबेस में सुरक्षित हो — तो यह करुणा छिन जाती है। स्मृतियों का बोझ असहनीय हो जाता है।

यही वह क्षण है जब चेतना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विद्रोह करती है। यह विद्रोह किसी मशीन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस 'अपरिपक्व मनुष्यता' के खिलाफ है जिसके हाथ में डिजिटल हथियार लग गए हैं।

निष्कर्षः शून्य को बचाने का साहस

हम 'ईश्वरीय' सामर्थ्य वाले उपकरण तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर उन्हें संभालने वाला 'संयम' विकसित हुआ है? तकनीक भविष्य का ढांचा खड़ा कर सकती है, लेकिन उस ढांचे के भीतर प्राण केवल 'विवेक' और 'चेतना' ही फूँक सकते हैं।

यदि हम अपनी चेतना के स्तर को तकनीकी सामर्थ्य के बराबर नहीं उठा पाए, तो हमारी यह शक्ति ही हमारी सभ्यता के अंत का कारण बनेगी।

अंततः, प्रश्न यह नहीं है कि अक क्या करेगी — प्रश्न यह है कि इस मशीनी कोलाहल के बीच क्या मनुष्य अपने भीतर के 'शून्य' को बचा पाएगा?

* लेखक परिचय

रवि प्रकाश सिंह — लेखक, प्रशासक और चेतना, तकनीक तथा सभ्यता के भविष्य पर सार्वजनिक विचारक। उनकी आगामी विज्ञान-कथा पुस्तक 'शून्य के भीतरः चेतना का विद्रोह' इसी विमर्श को कथात्मक विस्तार देती है।

बस्तर में क्यों हो रही है सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग? योगी से लेकर मोहन यादव तक लेंगे हिस्सा, जानिए वजह!

(जीएनएस)।

कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग करने वाले हैं. इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे. आखिर इस मीटिंग के लिए बस्तर को ही क्यों चुना गया? आइए समझते हैं.

दशकों तक लाल आतंक और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने वाला छत्तीसगढ़ का बस्तर आज देश की राजनीति और सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं ऐतिहासिक बैठक हो रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बस्तर के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी हाई-लेवल और राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन इस क्षेत्र में किया गया है. इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हैं. यह बैठक न केवल राज्यों के आपसी समन्वय बल्कि बस्तर के बदलते स्वरूप का एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरी है.

50 की उम्र पार करने के बाद भी सिंगल हैं बॉलीवुड के ये 5 स्टार्स, अपनी शर्तों पर ऐसे जी रहे जिंदगी

(जीएनएस)।

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (रॅंल्ल डॅंल्ल) के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। दरअसल सलमान खान ने अपनी एक शर्टलेस तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। हालांकि तस्वीर से ज्यादा उसके कैप्शन ने लोगों का ध्यान खींचा था। भाईजान ने कैप्शन में लिखा था-अकेला रहना आपकी पसंद हो सकती है लेकिन तन्हाई तब महसूस होती है जब कोई आपके साथ रहना न चाहे।

सलमान खान को 60 की उम्र में अकेलेपन ने किया परेशान

इस लाइन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। लोग ये कयास लगाने लगे थे कि 60 की उम्र में सलमान खान को उनका अकेलापन परेशान कर रहा है। लोगों की मानें तो सलमान खान उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपने पास एक हमसफर को मिस कर रहे हैं।

सलमान खान का पोस्ट हुआ वायरल

आपको बता दें कि सलमान खान का सिंगल स्टेटस हमेशा चर्चा में रहता है। ऐसे में फैंस को लगा कि एक्टर शायद अपनी निजी जिंदगी को लेकर इमोशनल हो रहे हैं। यही वजह रही कि उनका पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया और हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी थी।

बॉलीवुड में कई स्टार्स ने 50 की उम्र तक भी नहीं की शादी

-जानकारी के अनुसार बॉलीवुड

में जहां कई स्टार्स अपनी शादी और फैमिली लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़े नाम भी मौजूद हैं जिन्होंने आज तक शादी नहीं की। दिलचस्प बात ये है कि इनमें कई ऐसे सेलेब्स हैं जिनके लाखों-करोड़ों फैंस हैं और जो दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं।

-कुछ स्टार्स ने अपने करियर को प्राथमिकता दी, तो कुछ को रिश्तों में निराशा मिली। वहीं कई कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक अपनी पसंद का जीवनसाथी नहीं मिला। यही वजह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी ये सितारे सिंगल लाइफ को पूरी आजादी और आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं।

इन सेलेब्स ने किया शादी न करने का फैसला

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के अलावा तब्बू, अक्षय खन्ना, अमीषा पटेल और डिनो मोरिया जैसे कई बड़े स्टार्स भी अब तक शादी से दूर हैं। इन सभी कलाकारों ने अलग-अलग वजहों से शादी न करने का फैसला लिया और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चुना। इन सितारों की निजी जिंदगी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। कई बार इनके अफेयर्स ने खूब सुर्खियां बटोरीं लेकिन रिश्ते शादी तक नहीं पहुंच सके।

बॉलीवुड के 5 स्टार्स जिन्होंने अभी तक नहीं की शादी

सलमान खान

-बॉलीवुड के सबसे चर्चित बैचलर्स की बात करें तो सलमान खान का नाम सबसे पहले आता है। 60 की उम्र के करीब पहुंच चुके सलमान खान आज भी इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाते हैं।

-सलमान खान का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ता रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनका रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चित रहा। फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। हालांकि इस रिश्ते का अंत काफी दर्दनाक था।

-सलमान खान का नाम संगीता बिजलानी, सोमी अली, कैटरीना कैफ और लूलिया वंतूर के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि इन रिश्तों के बावजूद उन्होंने कभी शादी नहीं की। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद सलमान खान ने शादी न करने का फैसला कर लिया था।

आखिर क्यों नहीं की सलमान खान ने शादी?

-सलमान खान की शादी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कई इंटरव्यूज में सलमान खान के पिता सलीम खान भी इस मुद्दे पर खुलकर बात कर चुके हैं। सलीम खान ने कहा था कि उनके बेटे सलमान खान रिश्तों में जल्दी जुड़ जाते हैं लेकिन शादी जैसा बड़ा फैसला लेने में हिचकिचाते हैं।

-सलमान खान के पिता ने बताया था कि उनका बेटा अपने परिवार और खासतौर पर अपनी मां जैसी पारिवारिक सोच रखने वाली पार्टनर चाहता है। वहीं सलमना खान के ज्यादातर रिश्ते इंडस्ट्री की सफल और करियर-ओरिएंटेड एक्ट्रेसेस के साथ रहे, जिसके चलते सोच में अंतर भी सामने आया।

भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के सीएम श्री मोहन चरण मांझी ने किया उद्घाटन

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भुवनेश्वर के मेफेयर कन्वेंशन में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी के साथ पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने पूर्वी भारत की कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने का सशक्त आह्वान किया। ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से जुड़े इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में दलहन-तिलहन उत्पादन, छोटी जोत वाले किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, किसान रजिस्ट्री, बागवानी, कृषि ऋण, विपणन, नकली कृषि आदानों पर नियंत्रण और किसान आय वृद्धि जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा का खाका रखा गया।

पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की कृषि, किसानों की आजीविका और क्षेत्रीय कृषि रणनीति को नई दिशा देने के लिए गंभीर विचार-विमर्श का मंच है। श्री चौहान ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ की पावन धरती पर एकत्र हुई यह 'टीम एग्रीकल्चर' पूर्वी भारत की खेती की हालत को बेहतर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प के साथ बैठी है। उन्होंने पूर्वी भारत की उर्वरा भूमि, जल उपलब्धता, विविध जलवायु और किसानों की मेहनत को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि थोड़े से सही प्रयासों से यही क्षेत्र भारत के कृषि विकास का ग्रोथ इंजन बन सकता है।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि जीवनदाता बताते हुए कहा कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और शक्तिशाली भारत की ओर बढ़ रहा है और इस यात्रा की रीढ़ कृषि है। उन्होंने कृषि के सामने तीन प्रमुख लक्ष्य रखे- 140 करोड़ देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,

पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराना और किसानों की बेहतर आजीविका व आय वृद्धि सुनिश्चित करना।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, नुकसान होने पर भरपाई करना और कृषि का विविधीकरण करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, बल्कि दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां और अन्य उच्च मूल्य फसलों की ओर भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पूर्वी भारत में इन सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों में छोटी जोत एक बड़ी वास्तविकता है, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग को केवल नारा नहीं, बल्कि जमीन पर उतरा हुआ मॉडल बनाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनाज के साथ फल, सब्जियां, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी जैसी गतिविधियों को जोड़कर छोटे किसान की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने आईसीएआर, कृषि मंत्रियों और अधिकारियों से आग्रह किया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल किसानों तक प्रेरक और व्यवहारिक रूप में पहुंचें।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने टिकाऊ कृषि की दिशा में मृदा स्वास्थ्य की रक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि बिना मृदा परीक्षण के अंधाधुंध खाद का प्रयोग खर्च भी बढ़ाता है और धरती की सेहत भी बिगाड़ता है, इसलिए किसानों को आवश्यकतानुसार ही उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती को भी प्रधानमंत्री के फोकस का क्षेत्र बताते हुए किसानों से अपनी जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने बताया कि 1 जून से 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से संतुलित खाद उपयोग, मिट्टी की सेहत, आधुनिक तकनीक, योजनाओं की जानकारी और किसान जागरूकता पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के डायवर्जन पर रोक लगानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी वाला खाद केवल किसान और खेती के काम में ही उपयोग हो। उन्होंने नकली खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशकों को किसानों के खिलाफ बड़ा अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कड़े कानून की आवश्यकता है और राज्यों को इस दिशा में सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, ताकि किसानों की लागत न बढ़े और उन्हें गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान मिल सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पूर्वी क्षेत्र देश को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि दाल और तिलहन की खेती को बढ़ावा तभी मिलेगा जब किसान को यह भरोसा होगा कि उसकी उपज की खरीद सुनिश्चित है, इसलिए पीएम-आशा, खरीद प्रणाली, नैफेड, एनसीसीएफ और राज्य एजेंसियों की भूमिका को और प्रभावी बनाना होगा।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने वैज्ञानिक शोध और तकनीक को खेत तक पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्रों और वैज्ञानिक संस्थानों का ज्ञान सीधे किसानों तक पहुंचे, यह समय की मांग है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे अपनी परिस्थितियों के अनुरूप विशेष अभियान चलाएं, ताकि रिसर्च, अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और योजनाओं की जानकारी समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचे।

उन्होंने फार्मर आईडी को किसान तक सुविधाएं सरल, पारदर्शी और तेज तरीके से पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बताया। उनके अनुसार फार्मर आईडी से किसान की जमीन, परिवार और अन्य विवरण एक जगह उपलब्ध होने से ऋण, उर्वरक वितरण और योजना लाभ में अनावश्यक देरी तथा परेशानी कम होगी, इसलिए इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री चौहान ने बागवानी, आम जैसी उच्च मूल्य फसलों, निर्यात क्षमता, स्वच्छ पौध सामग्री, नर्सरी व्यवस्था और बाजारोन्मुख कृषि पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के कई राज्यों में फल, सब्जियां और विशिष्ट फसलें न केवल देश के भीतर बल्कि निर्यात के स्तर पर भी किसानों को अधिक मूल्य दिलाने की क्षमता रखती हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पूर्वी राज्यों के लिए कृषि भविष्य का साझा रोडमैप तैयार करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मेलन पूर्वोदय की परिकल्पना को बल देगा और पूर्वी भारत की कृषि उत्पादकता, जलवायु-अनुकूल खेती और समावेशी कृषि विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

सीएम योगी बोले - यूपी में रूल ऑफ लॉ, अपराधियों में भय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार आदि क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन आया।

(जीएनएस)।

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में रूल ऑफ लॉ है। अपराधियों में भय है। बीते 9 वर्षों के दौरान यूपी में कानून-व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार आदि क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की संकल्पना का साकार रूप हम सभी को प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वह मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद को संबोधित कर रहे थे।

योगी ने कहा कि अतीत में चुनौतीपूर्ण रहा यह अंचल आज राष्ट्रीय नीति-निर्धारण की मुख्यधारा

में शामिल हो गया है। पीएम ने सहकारी संघवाद पर आधारित 'टीम भारत' का विजन दिया है, जिसमें क्षेत्रीय परिषद महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिषद पूरी सक्रियता से आगे बढ़ रही हैं। जो यूपी कभी एक बीमारू राज्य था, आज पूरे देश के विकास की धुरी बना है।

प्रदेश सरकार ने किसान, महिला, गरीब और वंचितों के उत्थान हेतु अनेक कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन से वर्ष 2026 तक 91.25 फीसदी परिवारों को पाइप पेयजल मिल रहा है। यह मिशन सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं से 900 मेगावॉट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न कर रहा है। साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित हैं। ई गवर्नेंस में यूपी अग्रणी है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 54 विभागों की 359 सेवाएं उपलब्ध हैं।

एआई और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण बजट का प्रावधान किया है। लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह पुष्टाहार दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों पात्र व्यक्तियों को निशुल्क उपचार मिल रहा है। अमृत योजनाओं से नगरीय विकास हो रहा है। स्कूल चलो अभियान से लाखों बच्चों का नामांकन हुआ। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर शून्य है, जो उल्लेखनीय प्रगति को दशार्ता है।

श्रमिक समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़

सीएम ने कहा कि श्रमिक हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं इसलिए औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ श्रमिक हितों और न्याय की रक्षा भी जरूरी है। प्रत्येक श्रमिक का सम्मान और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस उद्देश्य से लेबर ई-कोर्ट 'श्रम न्याय सेतु' लॉन्च किया है। विवाद निपटारे में दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित की गई है।

नमाज पर सीएम योगी के बयान पर अबू आजमी बोले, 'जैसे दुनिया चलती है, वैसे ही हमारा देश भी चलेगा'

(जीएनएस)।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करने संबंधी बयान के बाद देश भर में राजनीति तेज हो गई है. इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये बहस का कोई मुद्दा नहीं है. ये सब पोलराइज करने के लिए हिंदू-मुस्लिम किया जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है.

उन्होंने आगे कहा, "आज हालात बेहद खराब हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं हैं, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, ये सारी चीजें चल रही हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, अरे भाई जो जमाने से चीजें होती आई हैं, जैसे देश चलता है, दुनिया चलती है वैसे ही हमारा देश भी चलेगा."

'AI आ गया है और ये मंदिर-मस्जिद के पीछे पड़े हैं'

सपा नेता ने ये भी कहा कि यहां एक अलग ही चीज हैं, दुनिया कहां से कहां जा रही है. एआई का जमाना

आ गया और ये मंदिर-मस्जिद के पीछे पड़े रहते हैं. हमारा मतलब है कि इस देश का इतना प्यारा संविधान है, यहां हर धर्म के लोग रहकर के अपने देश के लिए जान दे सकते हैं."

गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी- अबू आजमी

वहीं, महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर बैठक पर सपा विधायक ने कहा, "बकरीद से पहले हर साल मुख्यमंत्री, कमिश्नर और सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक होती है. लेकिन इस बार बैठक बहुत संक्षिप्त रही और इसकी अध्यक्षता सिर्फ मुख्यमंत्री ने की. हर साल यह चर्चा होती है कि अगर वाहनों में कोई समस्या हो या जरूरत से ज्यादा जानवरों का परिवहन किया जा रहा हो, तो पुलिस जांच करेगी. लेकिन कुछ संगठन गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं.

'ये गाड़ियां रोककर 10-20 हजार रुपये ले लेते हैं'

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है कि कोई दूसरा इसमें हाथ नहीं लगा सकता है. उस पर केस भी किया जाएगा. केस हुए भी हैं लेकिन इनकी आदत सुधर नहीं रही है. ये गाड़ियां रोककर 10-20 हजार रुपये ले लेते हैं. कई उनको मारते हैं तो कहीं गाड़ियों से जानवर उतरवा लेते हैं. इस तरह की घटना अभी भी दो-तीन जगह हुई है. त्योहार है, 10 दिन अच्छी तरह से गुजर जाए."

नमाज को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा?

बकरीद से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नमाज पढ़नी है, तो शिफ्ट में पढ़िए या अपने घर के अंदर पढ़िए, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे. सड़कें रोकने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है.

मिजार्पुर 'जिम जिहाद' केस में सीएम योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर में जिम जिहाद और धर्मांतरण के मामले में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख देखने को मिला है. सीएम योगी के आदेश पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लव जिहाद गैंग के दस आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

मिजार्पुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण साजिश मामले में सीएम योगी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी मौलवी खलीलु रहमान, जिम ट्रेनर इमरान खान समेत 10 आरोपियों पर संगठित लव जिहाद का गिरोह चलाने का आरोप है. जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है.

हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण की साजिश

जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ हिन्दू महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें निशाना बनाते थे. आरोपियों ने जिम आने वाली सैकड़ों हिंदू महिलाओं को बहला-फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाया और फिर उनके धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता था. पुलिस की टीम इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही हैं. घाट

सीएम योगी के निर्देश पर सख्त एक्शन

पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना इमरान खान अपने साथियों के साथ जिम में आने वाली हिन्दू महिलाओं को अपना शिकार बनाता था. ये गिरोह ट्रेनिंग के बहाने महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने का काम करते थे, इसके बाद उन्हें फँसाकर संबंध बनाए जाते थे और आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था. पुलिस इस गिरोह से जुड़े और लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस ने कहा कि यूपी में महिलाओं से जुड़े किसी भी अपराध और उनके खिलाफ रची जा रही साजिशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि समाज में कड़ा संदेश जा सके और अपराधी अपराध करने से पहले हजार बार सोचें. पुलिस के इस एक्शन से आरोपियों में हड़कंप मच गया है.

चीता परियोजना: मजबूत प्रगति और उज्ज्वल भविष्य दशार्ती है भारत की ऐतिहासिक वन्यजीव पुनर्स्थापन पहल

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज चीता परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की प्रगति का आकलन किया गया और भविष्य की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना विशेषज्ञ और देश में वन्यजीव संरक्षण से जुड़े वरिष्ठ प्रक्षेत्र अधिकारी उपस्थित थे।

चीता परियोजना भारत में चीतों के विलुप्त होने के बाद उन्हें पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक अग्रणी पहल है। इस कार्यक्रम की शुरूआत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों के एक संस्थापक समूह को स्थानांतरित करके की गई थी, जिसमें समन्वित अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक योजना के माध्यम से बोत्सवाना से 9 चीतों को और शामिल किया गया।

वन्यजीवों के स्थानांतरण से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, इस परियोजना ने उत्साहजनक परिणाम दर्ज किए हैं। वर्तमान में चीतों की संख्या 53 है, जिनमें से 33 भारत में जन्मे हैं। यह भारतीय परिस्थितियों में सफल अनुकूलन और प्रजनन के कारण हुई महत्वपूर्ण वृद्धि को दशार्ता है। स्थानांतरित किए गए चीतों और उनके शावकों की उत्तरजीविता दर वैश्विक

मानकों के बराबर पाई गई है। कुछ मामलों में तो यह उनसे बेहतर भी है, जो वैज्ञानिक प्रबंधन और निगरानी प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

कार्यान्वयन कार्यलिपी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भूदृश्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान को आबादी की स्थापना के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जबकि गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को आगे विस्तार के लिए एक अतिरिक्त पयार्वास के रूप में तैयार किया गया है। ये स्थल मध्य भारत में फैले एक बड़े परस्पर जुड़े भूदृश्य का हिस्सा हैं, जो फैलाव और आनुवंशिक आदान-प्रदान को सुगम बनाते हैं। गुजरात के बन्नी घास के मैदानों सहित नए क्षेत्रों में परियोजना का विस्तार करने के लिए भी तैयारी कार्य चल रहा है, जहां पयार्वास की अनुकूलता और शिकार संवर्धन उपाय संतोषजनक स्तर पर पहुंच गए हैं।

वैज्ञानिक निगरानी से पता चलता है कि चीते भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अच्छी तरह से ढल रहे हैं। उनका विचरण स्थिर है, वे शिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रबंधन व्यवस्थाओं में कोई महत्वपूर्ण शरीर संबंधी तनाव नहीं देखा गया है।

परियोजना के अगले चरण में अतिरिक्त स्थानांतरणों के माध्यम से समेकन और विस्तार, मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जैसे नए स्थलों का विकास और चिन्हित भूभागों में एक मेटापॉपुलेशन ढांचे को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने और आबादी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी देशों से चीतों की निरंतर आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

चीता परियोजना लगातार प्रगति कर रही है और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल के रूप में उभर रही है। निरंतर वैज्ञानिक मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और समन्वित कार्यान्वयन के साथ, यह परियोजना दीर्घकालिक सफलता के लिए अच्छी स्थिति में है और देश में चीता संरक्षण और खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।

प्रधानों को लखनऊ जाने से रोका, पुलिस ने खुद ही लिया ज्ञापन

(जीएनएस)।

संभल। असमोली ब्लॉक के ग्राम प्रधानों को मंगलवार की शाम लखनऊ जाने से पुलिस ने रोका है। ग्राम प्रधान लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। पुलिस ने मौके पर ही प्रधानों से ज्ञापन लिया है।

अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रधान ब्लॉक में इकट्ठा हुए थे। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने पर उन्होंने प्रधानों से बातचीत की। पुलिस ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन शासन और प्रशासन को भेज दिया जाएगा। प्रधानों ने पुलिस की बात मानते हुए ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में पंचायत चुनाव समय पर कराने या वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। प्रधानों ने पंचायतों के अधिकारों की रक्षा और ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की अपील की। उन्होंने प्रशासक व्यवस्था लागू होने की आशंका जताई, जिससे पूर्व में समस्याएं हुई थीं। प्रधानों ने कहा कि चुनाव होने तक कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

लखनऊ बार एसोसिएशन के समर्थन में अधिवक्ता संघ ने किया प्रदर्शन

(जीएनएस)।

केराकत/बदलापुर। लखनऊ बार एसोसिएशन के समर्थन में बुधवार को केराकत और बदलापुर अधिवक्ता संघ ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने न्याय पालिका, अधिवक्ताओं के सम्मान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाई। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सड़क किनारे बने अधिवक्ता चेम्बरों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसे लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनके सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए सभी बार संघों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। इस दौरान तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। न्यायिक कार्य के बहिष्कार के चलते वादकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मामलों की सुनवाई प्रभावित रही। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सुरेश कुमार,

नमःनाथ शर्मा, दिनेश शुक्ला, मुकेश शुक्ला, संजय चौबे, अनिल सोनकर, सुभाष सिंह, किशन पांडेय आदि मौजूद रहे। बदलापुर : लखनऊ में अधिवक्ताओं का चेंबर तोड़कर उन पर लाठीचार्ज करने के विरोध में मंगलवार को तहसील के अधिवक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर चार सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम शिव प्रताप को सौंपा। संघ के अध्यक्ष राजदेव यादव की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने विरोध में जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए इंदिरा चौक पहुंचे। जहां से लौटकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। जहां वक्ताओं ने लखनऊ में हुई घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग किया। लोगों ने अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़ने व लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई किये जाने, तोड़े गए चेंबर बनवाने और क्षतिपूर्ति कराने, घायल अधिवक्ताओं की दवा आदि की व्यवस्था और आर्थिक सहायता देने व भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के मांगों का पत्रक एसडीएम के माध्यम से उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार को संबोधित कर सौंपा। इस मौके पर अशोक तिवारी, उदधि प्रकाश पाठक, अंबिका यादव, विष्णुदत्त शुक्ल, विवेक पांडेय, राजकुमार सिंह, राम अजोर, उपेंद्र मणि त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। संचालन महामंत्री जीतेंद्र कुमार सिंह ने किया।

डीएफएस ने दिवाला और संशोधन अधिनियम, 2026 पर आधे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया

(जीएनएस)।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अधिनियम, 2026 पर आधे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता डीएफएस सचिव श्री एम. नागराजू ने की। इसमें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे - नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल), इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) और एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड (एएसआरईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों और एग्जीक्यूटिव्स ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का आयोजन बैंकिंग क्षेत्र पर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के हालिया संशोधनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श करने और संहिता के संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों की समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था।

कार्यशाला के दौरान यह रेखांकित किया गया कि दिसंबर 2025 तक, संहिता के तहत 8,800 से अधिक कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) स्वीकार की गई थीं, जिसमें लेनदारों ने स्वीकृत समाधान योजनाओं के माध्यम से ₹4.11 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त किए और समाधान, समझौते, वापसी या अपील से जुड़े मामलों के बंद होने के माध्यम से 4,000 से अधिक कॉर्पोरेट देनदारों को संकट से बचाया गया।

डीएफएस सचिव श्री एम. नागराजू ने देश में एक समयबद्ध और क्रेडिटर-ड्रिवन दिवाला समाधान ढांचा स्थापित करने में आईबीसी द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस कानून ने समय पर कर्ज चुकाने की आदत को बढ़ावा दिया है। अब ध्यान कंपनियों को बंद करने के बजाय संकट में फंसी कंपनियों को दोबारा खड़ा करने और उनके मूल्य को अधिकतम करने पर केंद्रित किया गया है। ग्रुप इन्सॉल्वेंसी, क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी और लेनदार-प्रारंभिक दिवाला समाधान प्रक्रिया से जुड़े हालिया संशोधनों पर उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सुधार दिवाला ढांचे को और मजबूत करेंगे तथा समाधान में होने वाले विलंब को दूर करेंगे।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल ने संस्थागत क्षमता को मजबूत करने, लेनदारों का भरोसा बढ़ाने और दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में आईबीसी की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हालिया संशोधनों से हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार होगा और यह सुनिश्चित होगा कि दिवाला समाधान ढांचा कुशल, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार रहे।

कार्यशाला में एमसीए और आईबीबीआई द्वारा हालिया संशोधनों और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) तथा अन्य हितधारकों पर उनके प्रभावों पर प्रेजेंटेशन दी गईं। इन चर्चाओं से संहिता के संशोधित प्रावधानों को लागू करने से जुड़े कानूनी और परिचालन संबंधी ऑपरेशनल पहलुओं पर अधिक स्पष्टता मिली।

अपने समापन भाषण में, डीएफएस के विशेष सचिव श्री संजय लोहिया ने समाधान प्रक्रियाओं में तेजी लाने, रिकवरी में सुधार करने और एसेट्स के मूल्य को अधिकतम करने में आईबीसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। उन्होंने समाधान में होने वाली देरी, संस्थागत क्षमता की कमी और लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया, साथ ही यह भी रेखांकित किया कि आईबीसी ने भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्यशाला का समापन ऐसे विचार-विमर्श के साथ हुआ जिसने एक मजबूत, पारदर्शी और कुशल वित्तीय प्रणाली के सरकार के विजन के अनुरूप, वित्तीय संकट से जूझ रही परिसंपत्तियों के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के महत्व को और मजबूत किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने "सभी के लिए स्वास्थ्य" के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत, न्यायसंगत, समावेशी और जन-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।

"वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना: एक साझा जिम्मेदारी" विषय पर सभा को संबोधित करते हुए, श्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के प्रति भारत के व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "एक समग्र-सरकार' और 'समग्र-समाज' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' (सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज) की दिशा में भारत की तेज प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभा को बताया कि भारत ने समुदायों के करीब ही व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में 1,85,000 से अधिक 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' स्थापित किए हैं।

महामारी की तैयारी और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की दिशा में भारत के प्रयासों पर जोर देते हुए, श्री नड्डा ने कहा कि सरकार भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तकनीक की बदलाव लाने वाली भूमिका पर जोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 880 मिलियन से ज्यादा विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान (यूनिक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी) बनाकर भारत के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और देखभाल की एक निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित होती है।"

श्री नड्डा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैमाने और प्रभाव पर भी जोर दिया। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों सहित लगभग 600 मिलियन लाभार्थियों को कवर करती है।

स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती भूमिका पर, मंत्री ने प्रतिनिधियों को बताया कि भारत ने हाल ही में 'भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रणनीति' लॉन्च की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "एआई का भविष्य नैतिक और मानव-केंद्रित सिस्टम बनाने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है।"

"दुनिया की फार्मेसी" के रूप में भारत की भूमिका को फिर से दोहराते हुए, श्री नड्डा ने सस्ती जेनेरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन में देश के नेतृत्व पर प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के योगदान को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत, भारत ने लगभग 100 देशों को लगभग 300 मिलियन वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध कराईं, जो वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग और एकजुटता के प्रति राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया, "एकजुटता की भावना के साथ, आइए यह सभा नीतियों को ठोस परिणामों में बदलने और साझा जिम्मेदारी को सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य में बदलने की दिशा में आगे बढ़े।"